

गोवा सरकार का बड़ा कदम! मांडवी-जुआरी नदियों पर सख्ती, जानकर झूम उठेंगे आप

वर्षिय सूची (Table of Contents):

- >> मुख्य अपडेट्स...
- >> पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता...
- >> सरकारी कार्रवाई का आयोजन...
- >> भवषिय की योजना...
- >> जनता को क्या करना चाहिए?...
- >> आपके सवाल, हमारे जवाब...
- >> महत्वपूर्ण संबंधित लिंक्स...

गोवा की मांडवी और जुआरी नदियों के तट पर अवैध रेत खनन और निर्माण की स्थितिको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने तेजी से कदम उठाए हैं। वन विभाग ने गंभीर पर्यावरणीय चेतावनी जारी करते हुए इन क्षेत्रों की वसितृत मैपिंग भी की है।

मुख्य अपडेट्स

- >> वन विभाग ने मांडवी और जुआरी नदियोंके तट के आसपास कई इलाकों को चन्हित किया है
- >> अनयितरति निर्माण, भूमिभराव और व्यावसायिक गतविधियों की जानकारी एकत्र की गई
- >> पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाने की स्पष्ट आशंका है
- >> क्षेत्रों की वसितृत मैपिंग अत्यंत समयरेखा में पूरी हो गई
- >> संबंधित विभागों को संरक्षणात्मक कार्रवाई के लिए सूचना सौपी गई
- >> बाढ़ नयितरण और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ योजना बनाई जा रही है

पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता

गोवा के ये नदियाँ प्राकृतिक संसाधनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालाँ इनके तट पर हो रहे गतविधियों से:

- >> पारस्थितिक संतुलन बगिड़ रहा है
- >> जल स्रोतों को प्रदूषित होने का खतरा है
- >> बाढ़ के समय आवश्यक जल प्रवाह प्रभावित हो रहा है

>> स्थानीय कृषि और Pisciculture पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है

सरकारी कार्रवाई का आयोजन

वन विभाग ने TCP (Town and Country Planning) विभाग को गंभीर स्थिति की सूचना देते हुए कदम उठाने की सलाह दी है। इसके तहत:

- >> अवैध गतिविधियों की पहचान करने की व्यापक प्रक्रिया आयोजित की गई
- >> भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण कर वसित मानचित्र तैयार करना हुआ
- >> प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत संरक्षणात्मक उपायों की सलाह दी गई

भविष्य की योजना

सरकार ने इन क्षेत्रों में स्थायी समाधान ढूंढने के लिए विकास योजना तैयार करने की घोषणा की है। इसमें शामिल है:

जनता को क्या करना चाहिए?

- >> अवैध गतिविधियों की जानकारी पर्याप्त सबूतों के साथ सरकार को दें
- >> स्थानीय प्रशासन को अपनी चर्चाएं व्यक्त करें
- >> पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय रहें

आपके सवाल, हमारे जवाब

अभी तक सरकार ने केवल चर्चाएं किये गए उन क्षेत्रों पर सख्त नजर डाली है। पूर्ण बंद का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन क्षेत्रों में कड़े उपाय उठाए जाने की संभावना है।

वसित मैपिंग वन विभाग द्वारा तैयार की गई है। अधिकारिक वेबसाइट पर या संबंधित विभाग से स्वीकृत प्रतियों की जांच की जा सकती है।

हाँ, नागरिक अपने स्थानीय प्रशासन को सूचित कर सकते हैं। यदि आपको ऐसी जानकारी है जो सरकार की मदद कर सकती है, तो आप उसे ऑनलाइन फॉर्म या स्थानीय कार्यालय में सबमिट कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण संबंधित लिंक्स

Reference Official Source: भारत सरकार - वन विभाग, गोवा